बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 170

विनिवेश के जोखिम

सरकार अपने नियंत्रण वाली तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अपनी हिस्सेदारी एक अन्य तेल उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) को बेचने की कथित तौर पर तैयारी कर रही है। इस हिस्सेदारी बिक्री के बाद एक विशाल तेल विपणन कंपनी वजूद में आएगी जिसका भारत में पेट्रोल पंपों के दो-तिहाई और शोधन क्षमता के 40 फीसदी और विमानन ईंधन स्टेशनों के भी बड़े हिस्से पर नियंत्रण होगा। हालांकि सरकार की रुचि बड़े आकार में अधिक नहीं दिखती है। उसकी नजर उस पैसे पर है जो उसे बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर आईओसी से मिलेगा। वर्तमान मूल्य पर यह हिस्सेदारी करीब 40,000 करोड़ रुपये की है। इतनी राशि मिलने पर सरकार को चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के सौदे हुए भी हैं। वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने एक अन्य तेल उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का इतनी ही राशि में अधिग्रहण किया था। आज की तरह उस समय भी हिस्सेदारी बिक्री का मकसद पेट्रोलियम क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के बजाय विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना ही था।

लेकिन यह एक विनिवेश कार्यक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी चलाने का कोई तरीका नहीं है। दावा किया जाता है कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को सक्षम ढंग से चलाने की इच्छुक है लेकिन ऐसा लगता है कि वह इन उपक्रमों को अपने खर्चे पूरा करने के लिए पैसे देने वाली बड़ी गायों से कुछ ज्यादा नहीं समझती है। आईओसी और बीपीसीएल दोनों ही उपक्रमों के शेयर इस संभावित बिक्री की खबर आते ही गिर पड़े। इससे पता चलता है कि निवेशकों की नजर में यह बिक्री इन दोनों कंपनियों के लिए कोई अच्छा विचार नहीं है। ऐसे फैसलों और समग्र तौर पर खराब प्रबंधन ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में खासा मूल्य विध्वंस कर दिया है। यह साफ होना चाहिए कि विलय के बारे में ऐसा कोई भी फैसला लेते समय कंपनियों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, खास तौर पर आईओसी के कोष और उसकी उधारी क्षमता के बारे में क्या किया जा सकता था?

इस समय आईओसी का शुद्ध ऋण 72,000 करोड़ रुपये से अधिक है और उसके पास नाममात्र नकदी ही है। उसने इस वित्त वर्ष के लिए पहले से ही 25,000 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय की योजना बना रखी है जो वास्तव में जरूरत से कम ही लगती है। आईओसी के चेयरमैन ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उनकी कंपनी अगले पांच-सात वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करना चाहती है। क्या बीपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी को खरीदकर अपना कर्ज और बढ़ाने की योजना आईओसी के पूंजी निवेश एजेंडे से मेल खाती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार पेट्रो-रसायन क्षेत्र को सक्षम बनाने के नाम पर इस खरीद को किस तरह सही ठहरा सकती है? इस कदम से इस क्षेत्र में पूंजीगत व्यय साफ तौर पर प्रभावित होगा।

सार रूप में कहें तो यह आईओसी की उधारी क्षमता और आंशिक सॉवरिन गारंटी का इस्तेमाल करने की एक कोशिश है ताकि सीधे उधार लेने के बजाय पैसे सरकारी खजाने में भेजे जा सकें। यह कुछ वैसा ही है जैसा इसने सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों में आकस्मिक देनदारियां बढ़ाने का काम किया है। भारतीय खाद्य निगम जैसी सार्वजनिक कंपनी में भी सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए ऐसा हो चुका है। इससे न तो निजी निवेश बढ़ेगा और न ही सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता बढ़ेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज के दौर में यह एक बुरी आदत बनती जा रही है।

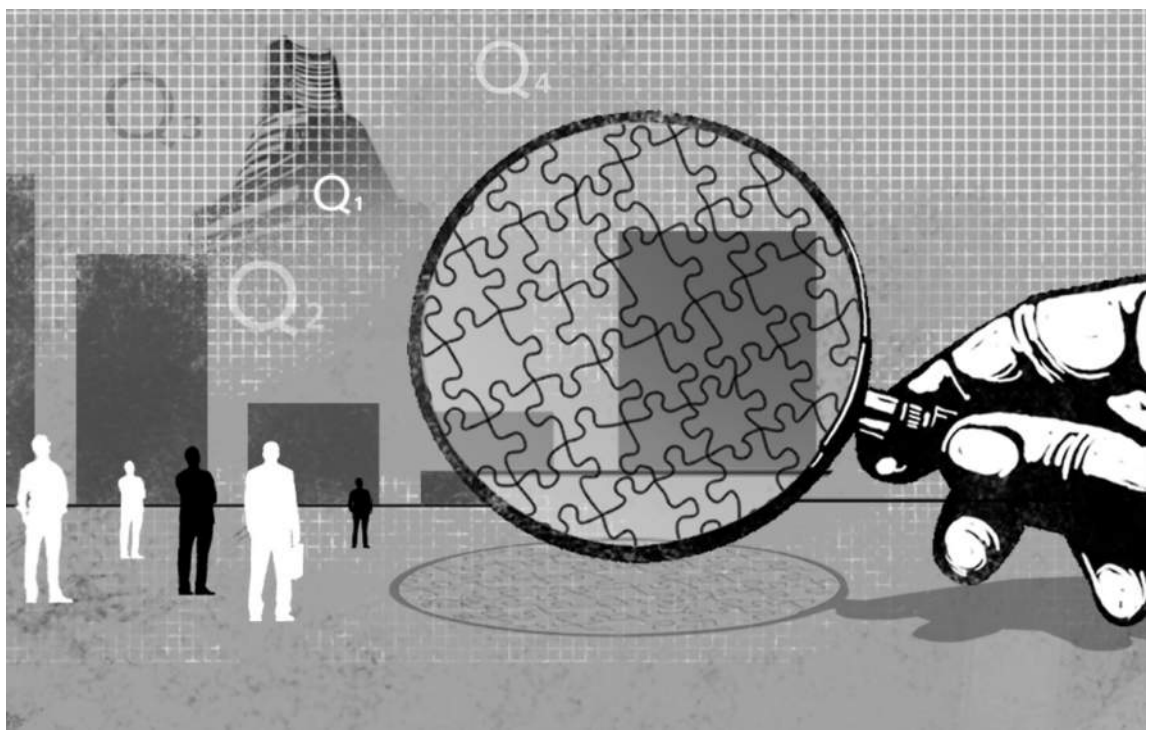

अजय मोहंती

वृहद आर्थिक प्रबंधन का समुचित आकलन

वृहद आर्थिक नीति के बेहतर आकलन के साथ आमतौर पर कुछ दिक्कतें जुड़ी रहती हैं। ऐसी ही तीन समस्याएं और उनके निराकरण के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं **अजय शाह**

कठिन वक्त में समय पर विश्वसनीय आंकड़ों का न हासिल हो पाना भी एक बड़ी समस्या है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाली कई व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है। आंकड़े भी देरी से प्राप्त होते हैं। सालाना आधार पर होने वाली वृद्धि दर भी तात्कालिक जानकारी नहीं देती। इन समस्याओं के तीन हल हैं। हमें ऐसे आंकड़ों पर जोर देना चाहिए जिनके आकलन के तरीके मजबूत हों। समय-समय पर होने वाला समायोजन, ताजा हालात के आकलन को आसान बनाता है।

भारत में हमें प्राय: वृहद आर्थिक दिक्कतों और वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में एक अहम बाधा है सूचना की कमी। चीजें कहां गलत हो रही हैं इसे समझने के लिए और समय पर हल तलाश करने के लिए जरूरत यह है कि हमारे पास ताजातरीन सूचना उपलब्ध रहे। मोटे तौर पर तीन समस्याएं हैं। पहली कमजोर कड़ी है सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता। आर्थिक जगत के आंकड़ों को देखें तो उसके कई तत्त्व अवधारणात्मक अथवा क्रियान्वयन संबंधी दिक्कतों भरे होते हैं। सीमित राज्य क्षमता के कारण इसका अनुमान तो होना ही चाहिए। अगर स्कूली शिक्षक पढ़ाने के लिए स्कूलों में नहीं आते हैं तो हमें उस समय आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए जब डेटा संग्रह के लिए जवाबदेह अधिकारी आंकड़े एकत्रित करने के लिए बाहर न निकलें। यह देखकर भी कतई चौंकने की आवश्यकता नहीं है कि देश की राज्य व्यवस्था द्वारा जुटाए गए आंकड़े खासे कमजोर होते हैं।

अगर वे भरोसेमंद हों भी तो भी वे खासी देरी से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगस्त महीना समाप्त होने वाला है लेकिन बैंक ऋण संबंधी ताजा आंकड़े जून महीने के हैं जबकि सीमेंट उत्पादन के आंकड़े मई के हैं। चालू खाता घाटा और सूचीबद्ध कंपनियों के बारे में मार्च की जानकारी ही उपलब्ध है। आंकड़ों की जानकारी रहस्यमय ढंग से शुरू और बंद होती रहती है। देश के आर्थिक समुदाय द्वारा साल दर साल आधार पर एकत्रित आंकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे उनकी गुणवत्ता और खराब होती जाती है क्योंकि ये काफी पुराने हो जाते हैं। साल दर साल आधारित आंकड़े चार तिमाहियों के औसत पर आधारित होते हैं। 2019 की चौथी तिमाही में दिखने वाली साल दर साल वृद्धि दर असल वर्ष की चारों तिमाहियों का औसत होती है।

इन समस्याओं से निपटने के अर्थशास्त्रियों के तीन तरीके हैं। पहला है मजबूत आकलन। हमारे देश में हम आंकड़ों का इस्तेमाल बिना आलोचना के आशावादी ढंग से नहीं कर सकते। डेटा के हर प्रयोगकर्ता को तमाम आंकड़ों को हासिल करने के तरीकों और उनके स्रोत पर पूर्ण आधिपत्य करना होता है। इसके बाद ही इनके भरोसेमंद होने के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। किस डेटा का भरोसा किया जा सकता है यह तय करना आसान नहीं है।

दूसरा हल सालाना वृद्धि से तिमाही वृद्धि के समय-समय पर समायोजित आंकड़ों पर स्थानांतरित होने में है। तिमाही दर तिमाही और बिंदु दर बिंदु शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर होता है। अगर हम पारंपरिक सालाना वृद्धि पर नजर डालें तो वर्ष 2019 की पहली तिमाही काफी हद तक 2018 की पहली तिमाही की तरह नजर आती है। इनमें एक वर्ष पहले की तुलना में 9.04 फीसदी और 8.81 फीसदी वृद्धि नजर आती है। ये काफी हद तक उचित नजर आते हैं। यदि मुद्रास्फीति की दर को 4 फीसदी मान लिया जाए तो वास्तविक वृद्धि दर 5 फीसदी के करीब ठहरती है।

सालाना आधार पर होने वाली बढ़ोतरी का हर पाठ कुछ और नहीं बल्कि तिमाही आधार पर हुए चार ताजातरीन अध्ययनों का औसत भर होता है। हमें बिंदु दर बिंदु सामयिक समायोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि दी गई अवधि में अर्थव्यवस्था किस प्रकार विकसित हुई। हमें इसे सालाना आधारित वृद्धि दर की धीमी सूचना के बरअक्स रखकर देखना होगा। उदाहरण के लिए हमने देखा कि 2017 की चौथी तिमाही से 2018 की तीसरी तिमाही तक वृद्धि में इजाफा हुआ और उसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। 2018 की तीसरी तिमाही में साल दर साल आधार पर वृद्धि में 17.38 फीसदी का सुधार दिखा लेकिन बिंदु दर बिंदु आधार पर इसमें 11.71 फीसदी की वार्षिक गिरावट नजर आ रही थी।

यहां दो दिक्कतें एक साथ नजर आती हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन के जो ताजातरीन आंकड़े हमें अगस्त 2019 में देखने को मिल रहे हैं वे जनवरी-मार्च 2019 तिमाही के हैं। वहीं पारंपरिक साल दर साल आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2019 तिमाही के आंकड़े अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तिमाही के औसत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जाहिर है यह जानकारी पुरानी है और ऐसे में वृहद अर्थव्यवस्था पर ताजा विचार प्रक्रिया को बाधित करती है।

कायदा तो यह है कि जब सालाना आधार पर वृद्धि बढ़े तो इसका अर्थ यह है कि बिंदु दर बिंदु भी काफी अच्छी और मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। उदाहरण के लिए 2017 की तीसरी तिमाही के 5.91 फीसदी से बढ़कर चौथी तिमाही में साल दर साल वृद्धि 10.12 फीसदी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चौथी तिमाही में बिंदु दर बिंदु वृद्धि बढ़कर 20.7 फीसदी हो गई थी।

भले ही हम सामयिक समायोजन की प्रक्रिया को अपना लें तो भी सितंबर 2019 में ही हम यह जान पाएंगे कि जून 2019 तिमाही में क्या हुआ था। हम बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? ऐसे में प्रमुख संकेतकों का निर्माण हमारी मदद कर सकता है।

तमाम वृहद आर्थिक और वित्तीय शृंखलाएं प्रमुख कारोबारी चक्र से संचालित नहीं होतीं। उदाहरण के लिए दुनिया भर में एक नियमन पर काफी जोर रहता है कि रोजगार थोड़ा ठहरकर प्रतिक्रिया देता है। अच्छा वक्त पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद ही नियोक्ता अपने यहां कर्मचारियों की नियुक्ति बढ़ाते हैं। वहीं बहुत गहरी कठिनाई आने के बाद ही कर्मचारियों को निकाला जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कारोबारी चक्र के साथ रोजगार शृंखला की प्रतिक्रिया थोड़ी थमकर आती है।

इसके उलट कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो प्रमुख संकेतक होते हैं। उनमें बदलाव कारोबारी चक्र में बदलाव आने से एक-दो तिमाही पहले ही नजर आने लगता है। भारतीय तिमाही समय शृंखला के हिसाब से देखें तो छह ऐसे संकेत हैं जो मुख्य कारोबारी चक्र को प्रभावित करते हैं: भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री, तिपहिया वाहनों का उत्पादन, कार उत्पादन, इक्विटी जारी होना, सीएमआईई कैपेक्स डेटाबेस में नई परियोजनाओं का शामिल होना और सीएमआईई कैपेक्स सूचकांक में मूल्य और इक्विटी अनुपात का स्तर। इनका औसत एक ऐसा सूचकांक प्रदान कर सकता है जो एक अहम संकेतक साबित हो सकता है। इसकी सहायता से हम कारोबारी चक्र के आरंभ में ही जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सियासी मोर्चे पर वाचाल मगर आर्थिक मोर्चे पर ठीक नहीं हाल

सम सामयिक
टीसीए श्रीनिवास-राघवन

इस लेख का जन्म उस सवाल से हुआ है जिसे इस समाचारपत्र के संपादकीय निदेशक ए के भट्टाचार्य ने कुछ दिनों पहले अर्थव्यवस्था पर दिए अपने व्याख्यान में उठाया था। उन्होंने पूछा था कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 1.76 लाख करोड़ रुपये के हस्तांतरण के मसले पर अपना पक्ष ठीक से क्यों नहीं पेश कर पाई है? आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे पर जारी विमर्श में विपक्षी नजरिया हावी हो रहा है?

यह सवाल एक बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत संदेशों और सरकार के राजनीतिक संदेशों को इतना प्रभावी ढंग से कैसे अंजाम दे लेते हैं? एक उद्धारक के तौर पर मोदी, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर तो उनके संदेश असरदार होते हैं लेकिन आर्थिक मामलों में संदेश इतने खराब क्यों हो जाते हैं?

अगर आप पीछे देखें तो 2002 से लेकर 2014 के दौरान मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते समय हालात इसके उलट थे। उस समय मोदी के आर्थिक संदेश देने की प्रक्रिया एकदम कारगर थी। आपको गुजरात मॉडल की चर्चा तो याद ही होगी? हालांकि उस समय वह व्यक्तिगत संदेश देने के मामले में उतने ही गलत थे।

विमल जालान और राकेश मोहन जैसे जाने-माने एवं निष्पक्ष अर्थशास्त्रियों पर सरकार के मत के हिसाब से चलने का आरोप कैसे लग रहा है? इनमें से कोई भी 'भाजपा हमेशा सही होती है' किस्म का भक्त नहीं है। कई दूसरे मामलों में भी यही कहा जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का ही मामला लीजिए। सांख्यिकीय मंत्रालय के प्रमुख एवं अपनी निगरानी में जीडीपी मापन की नई शृंखला बनवाने वाले प्रणव सेन मेरे भाई जैसे हैं। सेन के बाद उनकी जगह लेने वाले टीसीए अनंत तो वास्तव में मेरे बहुत करीब के चचेरे भाई हैं। वे लोग किसी भी मायने में भक्त नहीं हैं। असलियत तो ये है कि वे इसके ठीक उलट हैं।

नोटबंदी, बैंकिंग, एनपीए, रोजगार, निर्यात, विनिमय दर प्रबंधन और राजकोषीय घाटे के मामलों में सरकार सही संदेश देने में बुरी तरह नाकाम रही है। इसकी व्यापक असफलता काफी असामान्य है। इसकी तुलना में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के दौर की चिंताएं भी कमतर लगती हैं। हालांकि इससे भाजपा को चुनावी नुकसान होने की आशंका कम दिख रही है। लेकिन गाय की पूजा ही देशभक्ति का इकलौता पैमाना नहीं हो सकती है। देशभक्ति का एक अहम पैमाना यह भी है कि अपने ही लोगों की नजर में अपना देश बुरा न लगने लगे।

खुद अपनी दुश्मन

ऐसा नहीं है कि सरकारी नजरिया सौ फीसदी सही ही होगा और विपक्ष का नजरिया सौ फीसदी गलत ही है। लेकिन जहां तक आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रदर्शन का सवाल है तो सच्चाई सरकारी नजरिये से बहुत दूर नहीं है। फर्क बस इतना है कि वह इसे प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर पा रही है। ऐसे में प्रभावी राय एकदम उलट यह बन चुकी है कि आर्थिक मोर्चे पर सबकुछ चौपट हो चुका है।

मोदी मार्क-2 को इस विषय पर सोचने की जरूरत है और इस सोच से दूर ही रहना होगा कि संदेश देना महज एक चक्रीय समस्या है, संरचनात्मक नहीं। सच कहें तो यह विशुद्ध रूप से संरचनात्मक समस्या है। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री से होती है और इसकी जड़ें 2002 के दंगों के बाद उन पर लगातार हुए निजी हमलों से जुड़ी हैं।

मोदी विपक्ष और मीडिया को पूरी तरह नजरअंदाज करते रहे हैं। आपको 24 मई, 2013 को हिंदू बिज़नेसलाइन के अहमदाबाद संस्करण की शुरुआत के मौके पर दिया गया उनका भाषण सुनना चाहिए। उस समय मैं उसी समाचारपत्र से जुड़ा था। मोदी का संदेश साफ था, 'मुझे आपमें से किसी की भी जरूरत नहीं है'। आप इसे यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं।

अहम पदों पर बैठे या पहले आसीन रह चुके कई लोगों ने भी माहौल खराब करने में योगदान दिया है। इसने हालात को बदतर बनाने का काम किया है। इन लोगों में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कुछ अंशकालिक सदस्य और सांख्यिकी आयोग के कुछ पुराने सदस्य, आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर और एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। इन सबका मिलाजुला असर काफी विध्वंसकारी है।

यह महज संयोग नहीं है कि ये सभी लोग शिक्षक हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले प्रावधान में तो यकीन रखते हैं लेकिन तर्कसंगत निषेध लगाने वाले अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उनका यकीन नहीं होता है। अगर और कुछ नहीं तो शिष्टाचार ही आपसे संयमित आचरण की अपेक्षा रखता है।

इतना सब होने के बावजूद यह अपने आप में एक बुरी खबर है। उत्पादन वृद्धि की दर सुस्त होने का ताल्लुक रोजगार वृद्धि दर से जोड़ ही दिया जाता है। इनमें से किसी की भी व्याख्या बुरी खबरों के प्रबंधन से नहीं की जा सकती है। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए?

असली समस्या

मेरी नजर में समस्या कुछ ऐसी है: मुख्यमंत्री रहते समय मोदी मीडिया का ध्यान अपने से हटाकर अपने आर्थिक कदमों की तरफ ले जाने की कोशिश करते थे लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वह इसका ठीक उलटा काम करते रहे हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के किसी अधिकारी को मोदी से यह कहने की जरूरत है कि समस्या वह खुद हैं। पिछले प्रधानमंत्रियों के पास हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो उनसे यह बात बोल सकता था। पी एन हक्सर से शुरू होकर यह सिलसिला पुलक चटर्जी पर आकर खत्म हो जाता है। यह तरीका हमेशा कारगर नहीं रहा है लेकिन यह हमेशा नाकाम भी नहीं हुआ।

कानाफूसी

मंदी पर बयान

देश में आर्थिक मंदी की आहट सुनाई दे रही है। इस समय आर्थिक मंदी पर विशेषज्ञों से राय लेना आम रस्म जैसा बन गया है। ऐसे में सरकार और कारोबार दोनों जगह अहम पहुंच रखने वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने देश की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने वाली छोटी सी मजाकिया घटना का जिक्र किया। कुछ वर्ष पहले एक पत्रकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार जानने के लिए देर रात्रि में उन्हें फोन किया। उनका जवाब था, 'मैं पूरे दिन अर्थव्यवस्था को लेकर निश्चित नहीं था, तो अब क्या कह सकता हूं?' अगले दिन उन्होंने अपने स्टाफ से विजिटिंग कार्ड से मोबाइल नंबर हटाने के लिए कहा। हालांकि कई कंपनियों के बोर्ड में शामिल और शायद अब मंदी के बारे में ज्यादा सोच रहे उस व्यक्ति ने देश की आर्थिक स्थिति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, 'हां, मंदी का दौर है लेकिन मैं आशावादी हूं।'

जगह का महत्त्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 24, अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के सामने बना है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित थे। इस भवन से ठीक पहले भारतीय वायु सेना प्रमुख का आधिकारिक निवास है । यह भी प्रतीकात्मक है कि भारतीय वायु सेना प्रमुख के निवास में राफेल लड़ाकू विमान की प्रतिकृति बनी हुई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता का आरोप लगाया था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि गुजरात भवन और राफेल की प्रतिकृति की स्थिति का कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं पर गहरा असर पड़ेगा।

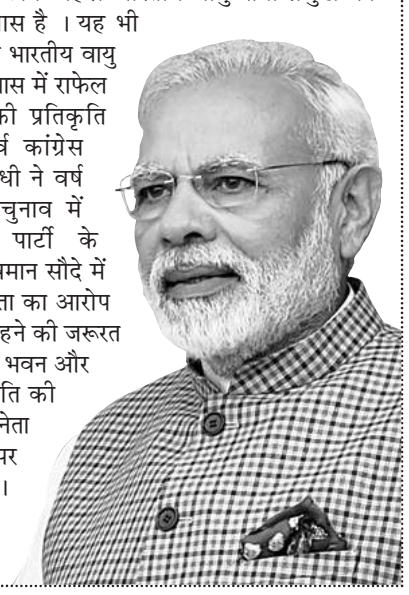

आपका पक्ष

असम में एनआरसी सूची जारी

सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी(एनआरसी) जारी कर दी है। इस सूची में लगभग 19 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। लेकिन पिछली सूची से करीब 20 लाख लोगों को राहत मिली है। लेकिन अभी भी 19 लाख लोगों की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस बार जारी सूची में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके सदस्यों के नाम पिछली सूची में थे लेकिन इस सूची से गायब है। अगर हम एनआरसी से प्रभावित लोगों की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार असम के कामरूप जिले के कुछ क्षेत्रों में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सिर्फ एक या दो सदस्यों के नाम पिछली सूची में नहीं थे। लेकिन इस बार पूरे परिवार का नाम ही सूची से गायब है। सवाल यह है कि अगर इनकी नागरिकता अवैध है तो पिछली सूची में इनके नाम कैसे शामिल किए गए। सरकार का कहना है कि जिनके नाम

असम में जारी एनआरसी सूची में अपना नाम देखती महिलाएं व अन्य लोग फोटो-पीटीआई

एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है वे अगले 120 दिनों में ट्रिब्यूनल में अर्जी दे सकते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि अगर एनआरसी से प्रभावित लोग ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार एनआरसी की अंतिम सूची में प्रभावित लोगों में से अधिकतर को ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को इस महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल के फैसले पर असंतुष्ट होने के बाद सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करने की बात कही गई है लेकिन क्या सरकार इस प्रक्रिया के दौरान उन लोगों को कानूनी सहायता भी मुहैया कराएगी, क्योंकि इस अंतिम सूची में जिनके नाम शामिल नहीं हैं उनमें से अधिकतर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। एनआरसी सूची से बाहर हुए लोगों को कानूनी सहायता भी मुहैया कराने की जरूरत है।

शुभम शर्मा, नोएडा

अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरे उपाय

मंदी की आशंका से गुजर रहे भारतीय उद्योग जगत की चिंता को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई उपायों की घोषणा की है। सीएसआर उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमे के बजाय दीवानी मुकदमा चलेगा। कंपनियों को अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और समय दिया गया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़े अधिभार को हटा दिया है। इक्विटी के दीर्घ एवं लघु अवधि पूंजी लाभ पर अधिभार बढ़ाने के फैसलों को भी वापस लिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ वाहन उद्योग को राहत दी गई है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक खरीदे गए सभी बीएस-4 मानक वाले वाहन अपनी पंजीकरण अवधि तक मान्य रहने, वाहन कर्ज सस्ता करने और कबाड़ नीति लाने समेत अन्य कदम शामिल हैं। इन उपायों से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और लोगों में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। इन सुधारों से विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।